

The US Administration stopped the supply of armaments to Pakistan not at the instance of the Government of India but because of public opinion created within America. It was not the achievement of the Government of India.

What are the factors according to the political analysis or the political assessment of the Government of India which warranted the US Administration to take a decision to resume the supply of arms or to lift the 10 year old embargo though, in fact, they did not maintain that assurance of that embargo as they supplied arms to Pakistan even after the dead line of 25th March 1971 which they had set? Secondly, what concrete steps do the Government of India propose to take to convince the US that this decision to supply arms to Pakistan will create instability and lead to confrontation in the sub-continent affecting the peace of three countries?

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN
His first question was what are the factors according to our assessment, which are responsible for the decision of the American Government to give arms to Pakistan. So far as my information goes they have not announced their decision. You cannot presume that it is so. In the history of relations between Pakistan and USA and Pakistan and India the basic point has been that the United States always tried to believe in the principle of balance of power in the sub-continent, in a way encouraging some sort of arms race there. The real answer for improving the relations between India and United States was that they must give up this posture of trying to play the balance of power. The specific thing that was told to us here was that United States no longer believes in the playing of balance of power thing in the sub-continent. Our basic point is that if they supply arms to Pakistan, it will create an atmosphere of confrontation between Pakistan and India

and it would be going back on this assurance given to India. Secondly he asked what we are doing about it. We have warned them even before Mr. Bhutto visited Pakistan. We have expressed our clear assessment of the consequences of supplying arms to Pakistan. My answers today and my statement today is one more further step in this direction.

MATTER UNDER RULE 377

REPORTED BEATING TO DEATH OF A HARIJAN BY POLICE IN SAGAR DISTRICT OF MADHYA PRADESH

अध्यक्ष महोदय मानीय शरद यादव चकि नए नए सदस्य चुन कर आये है इ तिए मै उन को बोलन की इजाजत देना है ।

श्री शरद यादव (जबलपुर) अध्यक्ष महोदय मध्य प्रदेश में सागर जिले में एक हरिजन की पुलिस इस्पेक्टर श्री जगदीश सिंह द्वारा मौत की गई और उन का सिफ घट्ट मिला है । आज तक उस थानेदार को गिरफ्तार नहीं किया गया है । एम कई काम मध्य प्रदेश में हरिजनों पर जुल्म बान हो रहे है जिन के बारे में मेठी सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है ।

कल की खबर है कि छत्तीसगढ़ में वहां के लोगों पर लाठी चार्ज किया गया उन्होंने माग की कि भूखे है और सरकार ने उन को बजाय अन्न के लाठिया दी । मैं स्वयं बिलासपुर जेल में 11 महीने रहा हू मुझे मालूम है कि वहां अकाल की क्या स्थिति है । लेकिन सरकार अन्न घोषित नहीं करती अगर स जो लोग अन्न मांगने है उन पर लाठी चार्ज करनी है । प्राणवायु सरकार जिस के सेठी जी मुख्य मंत्री है, वहां पर शासन चला रही है । जो कुछ यहा से कहा जाता है उसी का पालन होता है, कोई वस्तुस्थिति को देखना नहीं चाहता । मैं भारत के नीजवानों की

[श्री शरद् यादव]

श्रीग से बना देना चाहता हूँ कि इस तरह की प्राणवायु (आक्सीजन सिलिन्डर) वाली सरकार को वह अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे ही प्राणवायु सरकार के मुख्य मंत्री आज प्रान्तों में केन्द्रीय सरकार के नेताओं ने बैठा रखे हैं जिन में अफल नहीं है, और अकाल जैसी स्थिति को नहीं मानते हैं। . .

अध्यक्ष महोदय : आप हरिजनो के बारे में बात कीजिए। इस सरकार की आप द्वारा उठाए गए मसलें में कैसे सम्बन्ध बढना है। यह तो प्रान्तीय सरकार में सम्बन्धन है, न कि केन्द्र में।

श्री शरद् यादव : कैंस मन्टर का मसला नहीं है जब कि प्राणवायु सरकार जगह जगह प्रधान मंत्री ने बैठा रखी है। हम तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन मानते हैं। वहाँ प्रान्तीय शासन है ही नहीं। सेटी जी की कोई सरकार वहाँ नहीं है। वह तो आक्सीजन सिलिन्डर वाली सरकार है। यहाँ से जो आदेश होगा वही माना जायगा। यहाँ के लोग कहेगें तो अकाल घोषित कर देंगे, वैसे नहीं, और हमारे जैसे लोगो को जेल में बन्द करते हैं। छत्तीसगढ में भूख से मौत हो रही है। जबलपुर के निकट कुडम में भूख से मौत हुई लेकिन उस को वहाँ के अधिकारी नहीं लिख। आप ने ऐसे प्राणवायु मुख्य मंत्री बैठा रखे हैं जो मौत और भूख से भी नहीं डरते हैं। तो मैं श्रीमती इंदिरा गांधी और उन के पाले हुए चमचो को बताना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान का नौजवान यह बातें बर्दाश्त नहीं करेगा। आज देश का नौजवान विगडी हुई व्यवस्था के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। गरीबी हटाओ और मूठ बोल कर के जो आपने गलत बहुमत पाया है यह ठीक नहीं है। . . .

अध्यक्ष महोदय : किसी वजह से मैंने आप को इजाजत दी थी, वह बात तो आप ने छोड़ दी और बातों में पड़ गए। अभी कुछ

देर समझने की कोशिश करें। अभी बहुत बक्त है आप के लिए पहले दिन ही न सब निकाल लीजिए।

We will adjourn now and re-assemble at 2.30 p.m.

The Lok Sabha adjourned for lunch till thirty minutes past Fourteen of the Clock

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at thirty-five minutes past Fourteen of the Clock

[MR DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

INDIAN TARIFF (AMENDMENT)
BILL

MR DEPUTY-SPEAKER *Indian Tariff (Amendment) Bill. Shri Vishwanath Pratap Singh to move the motion for consideration*

THE DEPUTY MINISTER IN THE
MINISTRY OF COMMERCE (SHRI
VISHWANATH PRATAP SINGH .
Mr Deputy-Speaker, Sir, I beg to
move

"That the Bill further to amend the Indian Tariff Act, 1934, be taken into consideration"

This Bill proposes to amend the First Schedule of the Indian Tariff Act, 1934 to give effect to the recommendations of the Tariff Commission regarding the continuance of protective duty beyond 31st December, 1974 to sericulture industry and intermediate dye stuff industry.

As regards the intermediate dye stuff industry, till now, 56 items were included in the protective duty upto December, 1974. In this Bill, it is proposed, apart from 56 items, to add 14 more items for protective duty and, for sericulture industry, the existing rate of protective duty is proposed to be continued.

The Bill was brought in the last session on 20th December. The Bill was introduced. But as the House was